



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2012/अग्रहायण 20, 1934

No. 276]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2012/AGRAHAYANA 20, 1934

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2012

विषय : चीन जन.गण. कोरिया गण. और थाइलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित मोटर वाहनों में प्रयुक्त 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास आकार के काष्ट एल्युमिनियम एलॉय व्हील्स या एलॉय रोड व्हील्स चाहे उनके साथ सहायक सामग्री हो या न हो, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

फा.सं. 14/7/2012-डीजीएडी.- यतः एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी सदस्य कंपनियों में से एक कंपनी अर्थात् मै० सिनर्जीज कार्स्टिंग्स लि० (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने " चीन जन.गण. कोरिया गण. और थाइलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित मोटर वाहनों में प्रयुक्त 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास आकार के काष्ट एल्युमिनियम एलॉय व्हील्स या एलॉय रोड व्हील्स " के पाटन का आरोप लगाते हुए, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरु करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटनरोधी वस्तुओं का अभिज्ञान उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण और संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह पाया है कि आरोपित किसी पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को

हुई "क्षति" तथा आरोपित पाटन और "क्षति" के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त साक्ष्य है जिससे पाटनरोधी जांच की शुरुआत न्यायोचित ठहरती है; प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार आरोपित पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच शुरु करते हैं।

### विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद " चीन जन.गण, कोरिया गण. और थाइलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित मोटर वाहनों में प्रयुक्त 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास आकार के काष्ठ एल्युमिनियम एलॉय व्हील्स या एलॉय रोड व्हील्स " है।

4. एलॉय व्हीलों या एलॉय रोड व्हीलों (ए आर डब्ल्यू) का उत्पादन विभिन्न आकारों/व्यासों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मोटर वाहनों में प्रयुक्त केवल 12 इंच से 24 इंच तक व्यास आकार के ए आर डब्ल्यू शामिल हैं। 12 इंच से 24 इंच व्यास से भिन्न ए आर डब्ल्यू उत्पाद क्षेत्र से बाहर हैं। वस्तु में प्रसंस्कृत या अर्धप्रसंस्कृत ए आर डब्ल्यू शामिल हैं चाहे वे पेंट किए गए हों या न किए गए हों या कोम प्लेटेड हों। ए आर डब्ल्यू का मुख्य कार्य यह है कि इन्हें मोटर वाहन की गति हेतु उनमें लगाया जाता है। मोटर वाहनों के लिए व्हील आम तौर पर इस्पात या एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। आवेदक के दावानुसार एलॉय व्हील नई पीढ़ी के उत्पाद हैं और इस्पात व्हीलों की तुलना में इनमें बेहतर विशेषताएं होने के कारण ये भारत के बाजार में व्यापक रूप से कब्जा कर रहे हैं। इस्पात व्हील उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं। ए आर डब्ल्यू सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 87 के सी.शु. उपशीर्ष सं. 8707.70 के तहत "रोड व्हील्स और उनके पुर्जे तथा सहायक सामग्री" विवरण के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

### घरेलू उत्पाद का आधार

5. यह आवेदन एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अपनी सदस्य कंपनियों में से एक कंपनी अर्थात् मै. सिनर्जीज कास्टिंग्स लि० की ओर से दायर किया गया है। आवेदक के दावे के अनुसार भारत में विचाराधीन उत्पाद के दो अन्य उत्पादक हैं। आवेदक का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का "एक बड़ा भाग" बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन में उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार संबंधी मानदंड की पूर्ति होती है।

### समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि जिस संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समनुरूप है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं में तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य तथा अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" माना जा रहा है।

## शामिल देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण., कोरिया गण. और थाइलैंड हैं ।

## सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन.जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए । आवेदक ने यह कहते हुए भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत का प्रतिफल उपलब्ध नहीं है । जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है । गैर बाजार अर्थव्यवस्था के उपर्युक्त अनुमान के मददेनजर और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है ।

9. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह कोरिया गण. में किसी एक उत्पादक से कीमत सूची प्राप्त कर सकता है और कोरिया गण. के मामले में उस पर भरोसा किया जाता है ।

10. आवेदक ने थाइलैंड के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत का वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया है । यद्यपि उसने अनुरोध किया है कि सभी संभव प्रयास किए गए थे । चूंकि थाइलैंड से ऐसी कोई प्रामाणिक तथा भरोसेमंद सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी इसलिए लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा शासित कीमत और थाइलैंड की विद्युत दर के आधार पर एल्युमिनियम की कीमतों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है ।

## निर्यात कीमत

11. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का अनुमान आवेदक द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विसेज प्रदत्त सौदे-वार आयात आंकड़ों पर विचार कर लगाया गया है । पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन तथा ऋण लागत के लिए कीमत समायोजन निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए किया गया है । पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का पर्याप्त साक्ष्य है ।

## पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना कारखाना स्तर पर किया गया है जिससे प्रथमदृष्टया या संबद्ध देशों के बारे में पर्याप्त पाटन मार्जिन का पता चलता है । इस बात का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय

बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है । पाटन मार्जिन के बारे में न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है ।

### क्षति एवं कारणात्मक संबंध

13. आवेदक ने पाटित आयातों की संवर्धित मात्रा, कीमत कटौती तथा लाभप्रदता में गिरावट, घरेलू उद्योग के लिए लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट के रूप में आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप हुई "क्षति" के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है । पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हो रही "क्षति" का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ।

### जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि जुलाई, 2011 से जून, 2012 तक की है । तथापि, क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 09 से मार्च, 2010, मार्च, 2010 से अप्रैल, 2011, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 और जांच अवधि के आंकड़ों पर विचार किया गया है ।

### सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है और निम्नलिखित को लिख सकता है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग,  
कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

### समय सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 (चालीस) दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करें । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम

दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समयावधि में विस्तार हेतु किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे (क) गोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) चिह्नित और (ख) अगोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) चिह्नित दूसरे सैट के रूप में दो पृथक सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" उल्लिखित होना चाहिए।

18. किसी गोपनीय चिन्हांकन के बिना प्रस्तुत सूचना अगोपनीय मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता हेतु प्रदत्त सूचना के साथ इस आशय का एक बेहतर कारण संबंधी विवरण प्रदान करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

20. अगोपनीय रूपांतरण जिस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय-वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो इस आशय के कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

21. प्रस्तुत की गई सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है और सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है या वह सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. किसी सार्थक अगोपनीय सारांश के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में बेहतर कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है। प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत इसका प्रकटन ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को नहीं करेंगे।

4558 9/12-2

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

23. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं । कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

**असहयोग**

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2012

**Subject :** Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches, originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.

**F. No. 14/7/2012-DGAD.**—Whereas, the Aluminum Association of India, on behalf of one of its member companies namely M/s-Synergies Castings Limited (hereinafter referred to as the applicant), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of "Cast Aluminum Alloy Wheels or Alloy Road Wheels used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches", originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand, for initiation of anti-dumping investigation and for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

2. **AND WHEREAS,** the Authority finds prima facie that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration in the present application is "Cast Aluminum Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches", originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.

4. Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) are produced in various sizes/diameters. The product under consideration covers only ARWs of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches used in motor vehicles. ARWs other than 12 inches to 24 inches diameter are out of the product scope. The goods include finished or semi-finished ARWs whether unpainted, painted or chrome plated. The main function of ARWs is that they are fitted on motor vehicles to enable vehicle movement. Wheels for Motor Vehicles are generally made of Steel or Aluminium Alloy. As claimed by the applicant Alloy Wheels are new generation product and are widely capturing market in India because of their superior features over the steel wheels. Steel wheels are not included in the product scope. ARWs are classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading No. 8708.70 under the description "Road wheels and parts and accessories thereof". However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

**DOMESTIC INDUSTRY STANDING**

5. The application has been filed by Aluminium Association of India on behalf of one of its member companies namely M/s-Synergies Castings Limited. As claimed by the applicant there is two other producers of the product under consideration in India. The production of the applicant accounts for "a major proportion" in the total production of the product under consideration in India. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**LIKE ARTICLE**

6. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Anti-dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated prima facie as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

**COUNTRIES INVOLVED**

7. The countries involved in the present investigation are China PR, Korea RP and Thailand.

**NORMAL VALUE**

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para-7 and

4558 4/12-3

8 of Annexure-I to the Rules. The applicant has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted; stating that consideration of cost or price in a market economy third country is not available. The Normal value claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

9. The applicant has submitted that they could procure a price list from one of the producers in Korea RP and the same is relied upon for normal value in case of Korea RP.

10. The applicant did not provide actual evidences of price of subject goods in the domestic market of Thailand even though they submitted that all possible efforts were taken. Since any such authentic and credible information could not be collected for Thailand, the normal value is constructed by considering the Aluminium prices on the basis of prices governed by London Metal Exchange and electricity rate of Thailand.

#### **EXPORT PRICE**

11. Export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transaction-wise import data as provided by the applicant from International Business Information Services. Price adjustments have been made on account of port expenses, inland freight, ocean freight, marine insurance, bank commission & credit cost to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of the export prices of the subject goods from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

#### **DUMPING MARGIN**

12. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows prima facie significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

#### **INJURY AND CAUSAL LINK**

13. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting and decline in profitability, return on capital employed and cash flow for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the applicant caused by the dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.



**PERIOD OF INVESTIGATION**

14. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from July 2011 to June 2012. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2009 to March 2010, April 2010 to March 2011, April 2011 to March-2012 and the period of investigation (POI) has been considered.

**SUBMISSION OF INFORMATION**

15. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Room No.240, Udyog Bhawan,  
New Delhi -110011.**

**TIME LIMIT**

16. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the Anti-dumping Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

**SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS**

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

### **INSPECTION OF PUBLIC FILE**

23. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

### **NON-COOPERATION**

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority